प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एंव निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 19 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 09 – 16 मई 2016 मूल्य पांच रूपए

क्या वीरभद्र इसी वर्ष विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहे हैं?

शिमला/शैल। क्या प्रदेश विधान सभा के चुनाव इसी वर्ष करवाये जा रहे हैं? यह सवाल पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक डा0 राजन सुशांत के इस आश्य के आये ब्यान के बाद राजनीतिक हल्कों में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल तो एक अरसे से सरकार गिरने और समय से पहले चुनावों की संभावना जताते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो कुछ सरकार और कांग्रेस संगठन के अन्दर घटा है यदि उसका राजनीतिक आकलन किया जाये तो समय पूर्व चुनावों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस समय सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नही है। यह कितनी गंभीर है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसका संकेत प्रधान महालेखाकार विधान में कैग रिपोर्ट रखने के बाद हुई अपनी पत्रकार वार्ता में पूरी स्पष्टता से दे चुके हैं। जी.डी.पी. का 40% और राज्य की राजस्व आय से 214% अधिक का कर्जभार होना अच्छे सूचक नहीं हैं। यदि केन्द्र राज्य के कर्जभार को एक मुश्त माफ नही करता है तो कभी भी वेतन अदायगी तक का संकट आ सकता है। वीरभद्र बतौर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस हकीकत से पूरी तरह परिचित हैं। लेकिन इस सबकी जानकारी होते हुए भी मुख्यमंत्री प्रदेश में जहां कहीं भी जा रहे हैं दिल खोलकर घोषणाएं कर रहे हैं जिनसे प्रदेश का राजस्व व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। इस परिदृश्य में जानकार जानते है कि इन घोषणाओं के 5% को भी व्यवहारिक शक्ल दे पाना संभव नही होगा। अगले वर्ष के अन्त में वैसे ही चुनाव होने है। लोग इन घोषणाओं पर अमल की अपेक्षा इसी वर्ष के अन्त तक करना शुरू कर देंगे। अमल में एक-एक दिन की देरी से सरकार की विश्वसनीयता और अपेक्षित राजनीतिक लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की राय में ऐसी घोषणाओं का लाभ उनके अमल की नौबत आने से पहले ही लिया जा सकता है।

संगठन में भी कांग्रेस के भीतरे की खींचतान बाहर आना शुरू हो गयी है। वीरभद्र ब्रिगेड का गठन और विघटन अपने में एक बड़ा राजनीतिक कदम था। एन जी ओ का नाम लेकर पार्टी के समानान्तर संगठन घोषित करना जिसमें प्रदेश के हर भाग से प्रतिनिधित्व था ऐसा कदम कुछ क्षेणों के सोच का परिणाम नहीं माना जा सकता। फिर जब ब्रिगेड से जुड़े नेताओ के खिलाफ सुक्खु ने कारवाई का कदम उठाया तो उस कदम को आगे बढ़ने से पहले ही जिस तरह से रोका गया उसके संकेत भी कुछ इसी दिशा की ओर इंगित करते हैं । ब्रिगेड के बाद विक्रमादित्य का विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के ब्यान पर वीरभद्र सिंह का यह कहना है कि चुनाव में विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं इसका अर्थ भी कुछ इसी तरह का संकेत है। इसके बाद प्रतिभा सिंह का भी यह कहना कि विक्रमादित्य अगला चुनाव लड़ सकते हैं और यदि जनता चाहेगी तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। राजनीतिक विश्लेष्कों की राय में ऐसे ब्यानों से संगठन और जनता की प्रतिक्रियाओं का विश्लेष्ण किया जाता है। विक्रमादित्य को प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना वीरभद्र की आश्वयकता और विवशता दोनों ही हैं और इसके लिये वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। विश्लेष्कों का मानना है कि जब विक्रमादित्य की सिफारिश पर तीन दर्जन से ज्यादा विधान सभा क्षेत्रों में समानान्तर सत्ता केन्द्र तैयार किये गये थे तो उसके पीछे यही धारणा बलवती थी और अब इसको फलीभूत करने का समय आ गया है।

इन सबसे ऊपर वीरभद्र पर सीबीआई और ईडी की जांच का दबाव है। कानून के जानकार जानते हैं कि इन मामलों का खत्म होना संभव नहीं है इसी वर्ष इन मामलों के चालान अदालत में पहुंच जायेंगे। इनमें गिरफ्तारी के लिये '' डीम्ड अरैस्ट '' की अवधारणा के तहत कभी भी चालान अदालत में आ जायेंगे। अदालत में चार्ज लगने की प्रकिया में ज्यादा से ज्यादा दो महीने का समय लग सकता है। लेकिन अन्त में चार्ज लगना तय है और इसके बाद राजनीतिक हल्को में पद छोड़ने की मांग उठ जायेगी। ऐसी मांग पर विपक्ष के साथ अपरोक्ष में अपने भी स्वर मिला सकते है। यह स्थिति आयेगी ही यह तय है। ऐसी स्थिति से बचने के लिये इसी वर्ष के अन्त तक चुनाव करवा लिये जाने को बेहतर विकल्प माना जा रहा है और इसके लिये वीरभद्र ने अपने विश्वस्तो से चर्चा करना भी शुरू कर दिया है।

फारखा की स्पेन यात्रा फिर चर्चा में

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन पिछले वर्ष स्पेन गये थे। उस समय उनकी इस यात्रा को लेकर विभाग ने पूरी गोपनीयता बनाये रखी थी। लेकिन जब हिमाचल भवन दिल्ली से इस यात्रा की चर्चा कुछ राजनीतिक हल्कों में जा पहुंची तो इस पर और भी कई निगाहें केन्द्रित हो गयीं। स्पेन जंहा पर्यटन के लिये जाना जाता है वहीं पर उसकी एक पहचान टैक्स हैवन के रूप में भी है। मुख्यमन्त्री का प्रधान सचिव होने के कारण फारखा के भी दोस्तों दुश्मनों की संख्या कम नही है। इसी परिप्रेक्ष्य में फारखा को अपनी इस यात्रा का मकसद विभाग के रिकार्ड पर लाना पड़ा है। फारखा ने सूचित किया है कि **As regards Hostelco exhibition at Barcelona, Spain, It is intimated that the main focus of the exhibition was on range of products and services and latest innovations in equipmet, products and services for the hospitality sector. No other country was touched.**

फारखा की इस सूचना पर विभाग में किसी ने गूगल सर्च करके वहां के आयोजन का ऐजैण्डा ही खोज निकाला। गूगल सर्च में जो समाने आया है वह इस प्रकार है **HOSTELCO. International Restaurant, Hotel and Community Equipment Exhibition is a 4 days event being held from 23rd October to the 26th October 2016 at the Fira de Barcelona Gran Via in Barcelona, Spain. This event is orgainesd by: Fira de Barcelona and the Federacion Espanola de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hosteleria, Colectividades e Industrias Afines (FELAC) with the collaboration of the Federacion Espanola de Hosteleria (FEHR) In Hostelco you will find all the innovations in the sectors of hospitality, restaurant business and communities.**

गूगल सर्च में जो सामने आया है उसके मुताबिक वर्सेलोना में 23 अक्तूबर 2016 से 26 अक्तूबर 2016 को एक चार दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की जानी है। ऐसे में इस प्रदर्शनी में भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये करीब एक वर्ष पहले हीवहां जाने की आवश्यकता क्यों पडी? इस प्रदर्शनी में भाग लेने से प्रदेश के पर्यटन को कैसे लाभ पहुंचेगा? फारखा की इस यात्रा के बाद अभी विभाग को पर्यटन में क्या लाभ हासिल हुआ है इसको लेकर कोई कुछ भी कहने को तैयार नही है। फारखा की इस यात्रा को लेकर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में कई तरह की चर्चाओं का दौर चल रहा है। वैसे नियमो के अनुसार ऐसी यात्राओं से पहले सरकार का इनका एजैंडा सौंपना और यात्रा के बाद उसका पूरा विस्तरित विवरण सौंपना आवश्यक होता है जो इस यात्रा में नही हुआ है और इसी कारण इस पर अब चर्चाएं शुरू हुई हैं।

As regards Hostelco exhibition at Barcelona, Spain, it is intimated that the main focus of the exhibition was on range of products and latest innovations in equipment, products and services for the hospitality sector. No other country was touched."

Addl. Chief Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh

अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है नाट्य कला:आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि नाट्य कला अभिव्यक्ति का ऐसा सशक्त माध्यम है, जो अंतर्मन को झकझोर कर समाज में फैली विषमताओं पर चोट करने के साथ-साथ चुनौतियों से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करता है।

वह शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हरियाणा कला परिषद् के तत्वावधान में आयोजित नाट्य उत्सव के अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल की धर्मपत्नी दर्शना देवी भी उनके साथ थी।

राज्यपाल ने कहा कि नाट्य कला ने हमेशा से जन चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी इसके माध्यम से भ्रूण हत्या के खिलाफ, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने जैसे अहम् विषयों का मंचन कर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि नाट्य कलाकार इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता लाएंगे ताकि हम अपनी समृद्ध संस्कृति की ओर मुड़ सकें। कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने कहा कि कला का दमदार प्रदर्शन जन भावनाओं को सकारात्मक बनाने में सक्षम है। उन्होंने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग तथा हरियाणा कला परिषद् से भविष्य में भी ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया और स्वच्छता व नशामुक्ति जैसे सामाजिक संदेश को प्रचारित करने का आह्वान किया।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि बेटा-बेटी में कोई भेद नहीं है तथा व्यावहारिक रूप से बेटियां लगभग सभी क्षेत्रों में आगे हैं। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो, जहां लड़कियों ने कीर्तिमान स्थापित न किए हों। उन्होंने कहा कि बेशक समाज बदल रहा है, लेकिन आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध समाज में हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। यह अधिक चिंताजनक है कि पढ़े-लिखे समाज में यह बुराई अधिक है। उन्होंने कलाकारों को नाट्क के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उठाने के प्रयासों के लिए बधाई दी।

उन्होंने इस मौके पर, अलंकार थियेटर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत 'द फस्ट टीचर' नाट्क का आनंद लिया। यह नाट्क चक्रेश कुमार द्वारा निर्देशित किया गया था और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' विषय पर आधारित था।

इस अवसर पर, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक मधुबाला ने राज्यपाल का स्वागत किया। हरियाणा कला परिषद् के निदेशक अजय सिंघल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

हरियाणा कला परिषद् के उपाध्यक्ष सुदेश शर्मा तथा शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने गेयटी थियेटर में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ओम प्रकाश शर्मा की शिल्प कला प्रदर्शनी, 'वेस्ट वाइल्ड वर्ल्ड 2016' का भी अवलोकन किया। ओम प्रकाश ने रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सामग्री व अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर विभिन्न वन्य प्राणी व खूबसूरत फूल के गुलदस्तों को बनाकर बेजोड़ उदहारण प्रस्तुत किया है।

इस मौके पर, राज्यपाल ने कहा कि ओम प्रकाश ने प्रदर्शनी के माध्यम से वन प्राणियों के प्रति जो प्रेम व संबंधों को उजागर किया है वह प्रशंसनीय है। वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। उन्होंने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से स्कूली बच्चों के साथ कलाकार की शिल्प कला कार्यशाला आयोजित करने का आग्रह किया ताकि इस विधा को जीवित रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित चेवड़ी गांव का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिले की सुन्नी तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव चेवड़ी का दौरा किया तथा तीन पहले बादल फटने के कारण लापता हुए पांच युवाओं के अभिभावकों को सांत्वना दी।

मुख्यमंत्री ने आशवासन दिया कि राज्य सरकार लापता युवाओं की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है तथा राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) ने पहले ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को प्रत्येक को 4 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। चार अन्य परिवारों को भी त्वरित वित्तीय राहत वितरित की गई है।

वीरभद्र सिंह ने एनडीआरएफ के प्रभारी के साथ मामले पर चर्चा की तथा लापता व्यक्तियों के परिजनों से भी बातचीत की।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITIGN TENDER

Sealed item /percentage rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer Kumarsain Division HP PWD . Kumarsain from the experienced contractors enlisted with HPPWD for B&Rs works so as to reach in this office on or before 10-6-2016 up to 10:30 A.M. and will be opened on same day at 11:00AM. in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may wish to be present.

The application for issue of tender form shall be received on 08-06-2016 upto 4:00 P.M. The tender form shall be issued against cash payment (non-refundable) on 09-06-2016 from 10:00AM to 4:00PM.

The Earnest Money in the shape of National Saving Certificate/Time deposit receipt of any recognized Bank in HP duly pledged in the name of XEN must accompany with each application for obtaining the tender form. The Executive Engineer reserves the right to reject the tenders without assigning any reason.

1. Name of Work: Improvement of Kotgarh to sudmu road km 0/0 to 2/100 (SH : Widening at Rd. 2/0 to 2/390 C/o PCC R/ Wall at Rd. 2/180 to 2/192.2/355, B/wall at Rd 2/195 to 2/260 and C./o RCC Hume Pipe culvert at Rd. 0/539 & 0187 i/c both side wing wall) Estimated Cost Rs.9,04,949/- Earnest Money Rs.18,100/- Time Six Months.

2. Name of Work : Improvement of Kirti Bhanana road Km 0/0 to 2/0 (SH: Improvement of curves at Rd. 0/975 to 1/025 and B/wall at Rd. 0/075 to 1/125) Estimated Cost Rs.3,71,891/- Earnest Money Rs. 7500/- Time Six Months.

3. Name of work : A/R & M/o on Baragaon Machinkhad roa Km 0/0 to 18/0 (SH: C/o PCC Road side drain at Rd. 4/0 to 5/0) Estimated Cost Rs.2.21,514/- Earnest Money Rs.4500/- Time Three Months.

4. Name of Work : C/o Balance work for civil work for Strengthening of existing School infrastructure RMSA in Govt. Sr Sec. School at Shiwan (SH: Site development & building potion) Estimated Cost Rs.9,95,124/-, Earnest Money Rs. 20000/- Time Six Months.

5. Name of Work : C/o Oddi Bagan road km 0/0 to 1/450 (SH: C/o 900 mm dia RCC Hume Pipe Culvert at Rd. 0/105,0/480,0/855& 1/150) Estimated Cost Rs.3,95,200/- Earnest Money Rs.7900/- Time Six Months.

6. Name of Work : A/R & M/o on type -II Qtr at CHC Kumarsain (SH: Dismantling , roofing, stone masonry & distempering etc) Estimated Cost Rs. 6,44,945/- Earnest Money Rs.12900/- Time Six Months.

7. Name of Work : A/R * M/o to Mechanical Sub-Division Workshop building at Kumarsin (SH : Painting, Distempering , Boundary wall , Toilet & R/wall) Estimated Cost Rs. 4,72,106/- Earnest Money Rs. 9500/- Time Three Months

8. Name of Work : C/o Lohrigarh Bharasa road Km 0/0 to 1/700 (SH P/L Kharanja Stone soling in km 0/0 to 1/500) Estimated Cost Rs.3,65,318/- Earnest Money Rs.7350/- Time Three Months.

9. Name of Work : Imp. Of link road from Jhameri Dharta to Manjaban Palsar road km 0/0 to 2/135 (SH: C/o Wire Crate R/wall at Rd. 1/685 to 1/695, PCC B/ wall at Rd. 0/890 to 0/905 & PCC R/ wall at Rd. 0/982 to 1/000) Estimated Cost Rs.3 2,92,961 /- Earnest Money Rs.5700 /- Time Three Months.

10. Name of Work : Imp. Of link road to village Sanawagi Km 0/0 to 2/085 (SH: P/l Kharanja Stone Soling in km 1/400 to 2/085& C/o 90mm dia Hume pipe Culverts at Rd. 2/040 i/c wing wall at Rd. 0/630 to 0/645 , 1/880 to 1/895 & c/o B/wall at Rd. 0/355 to 0/367 & 1/975 to 1/987) Estimated Cost Rs.8,95,985/- Earnest Money Rs.18000/- Time Six Months.

11./Name of Work: Imp. Of link road from Bagadharta to Lhaltudhar via Churath km 0/0 to 5/000 (SH: P/L Kharanja Stone Soling in km 0/0 to 0/300 & 0/500 to 0/700) Estimated Cost Rs.1,21,773/- Earnest Money Rs. 2500/- Time Three Months.

12. Name of Work : c/o of link road to village Shanand Km 0/0 to 1/450 (SH: C/o 900mm dia RCC Hume pipe culvert at Rd. 1/000 i/c both side wall) Estimated Cost Rs.1,99,770/- Earnest Money Rs.4000/- Time Three Months.

13. Name of Work : Imp. Of Ambulance road from Majaban to Bhutti km 0/0 to 1/090 (SH: P/L Kharanja Stone Soling in km 0/350 to 0/600 , C/o PCC R/ Wall at Rd.0/400 to 0/406, 0/550 to 0/556& 0/572 to 0/580) Estimated Cost Rs.2,81,720/- Earnest Money Rs.5700/- Time Three Months

14. Name of Work : M/T on link road to P.H.C. Baragaon Km 0/0 to 0350 (SH: M/T & c/o V-Shape drain in km 0/0 to 0/350 Estimated Cost Rs.4,18,090/- Earnest Money Rs.8400/- Time Six Months.

Terms an Conditions :

1. The contractors shall produce their latest registration /renewal of their registration /latest sale Tax clearance certificate and Pan No. along with their application.
2. The tender form shall be issued to those contractors who fulfill the eligibility criteria as per condition No. 28 of General Rules and Direction of contract agreement.
3. The Exemption of earnest money will not be entertained.
4. The single /conditional tender will up will be rejected.
5. The offer shall remain valid up to 90 days.

Adv. No.-0527/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

हिमाचल प्रदेश को साहसिक गतिविधियों के लिए 'सर्वश्रेष्ठ भारतीय गन्तव्य पुरस्कार'

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2016 के लिए साहसिक गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय गन्तव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए प्रदेश को 'लोनली प्लेनट मैगजीन' के पाठकों द्वारा चयनित किया गया है।

यह पुरस्कार मुम्बई में 'लोनली प्लेनट मैगजीन' द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक लाम्बा और पत्रिका के सम्पादक वरधान कौंडविकर की उपस्थिति में फिल्मी सितारों द्वारा प्रदान किया गया।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबन्धक अनिल तनुजा ने यह पुरस्कार जॉन इब्राहिम, राहुल खन्ना, सूरज पंचोली, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सना खान, फैमिना मिस इण्डिया क्लाऊडिया जैसे प्रख्यात फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति में प्राप्त किया। साहसिक गतिविधियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य का पुरस्कार न्यूजीलैंड को प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के समस्त पर्यटन उद्योग जगत को पुरस्कार जीतने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैम्पिंग, आईस-स्केटिंग, पैराग्लाईडिंग, एंगलिंग, रीवर राफटिंग, पर्वतारोहण, मांउटेन साईकलिंग, व्हीकल सफारी इत्यादि जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि निगम आने वाले समय में पर्यटकों को अनेक वृहद पैकेज देने की योजना बना रहा है, जिसमें आवास व भोजन, परिवहन व अनेक साहसिक गतिविधियों शामिल होंगी।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एक रिक्त पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदनकर्ता सामाजिक जीवन में विस्तृत ज्ञान, कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, जन संचार अथवा प्रशासन एवं शासन में अनुभव रखता हो तथा वह संसद सदस्य व किसी भी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश की विधान पालिका का सदस्य नही होना चाहिए। वह किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय में लाभ पद पर न हो और इसके अतिरिक्त, किसी व्यवसाय व व्यापार से भी जुड़ा नही होना चाहिए।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, तक होगा।

पात्र व इच्छुक उम्मीदवार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए अपना जीवन परिचय प्रशासनिक सुधार विभाग की वैबसाईट www-himachal-nic-in@ar से निर्धारित प्रपत्र डाऊलोड़ कर सचिव, प्रशासनिक सुधार, हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नम्बर-301, हि.प्र. सचिवालय शिमला-2 अथवा arbr-hp@nic-in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र पहुंचने की अन्तिम तिथि 22 जून, 2016 सांय 5 बजे तक है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

उद्योगों की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करें: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल की द्वितीय

बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त चालक, मोटर मैकेनिक, आशुटंकक तथा इलैक्ट्रिशियन, फिटर इत्यादि जैसे अन्य आम पाठ्यक्रमों को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि ये पाठ्यक्रम कौशल रोजगार के लिए अधिक अनुकूल होने के कारण उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तथा युवाओं को 'मार्किट रैडी' बनाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा का सॉफ्ट कौशल विकास, जिसमें संचार कौशल, भाषा एवं व्यवहार कौशल विकास पाठ्डक्रमों का हिस्सा होना चाहिए ताकि युवा विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर सकें। निगम को अब अपनी कार्यशैली की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, जिससे निगम के बारे में लोगों को पता चले और अधिक से अधिक बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकें।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश को भारत की कौशल राजधानी बनाने के लिए कौशल विकास को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों से लेकर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों, अकुशल कामगारों, बेरोजगार, महिलाओं, विशेष रूप से सक्षम तथा अन्य लाभहीन अथवा सीमांत समूहों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम की 65000 युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने के अतिरिक्त 51 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करने की परिकल्पना है।

बैठक में खुदरा एवं आतिथ्य क्षेत्रों के दो पायलट क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्यक्रम में स्नातक के 16 महाविद्यालयों को अल्प सूची में डाला गया तथा कांगड़ा जिला के रैहन में महिला पॉलीटैक्निक के लिए स्थल के चयन को अन्तिम रूप दिया गया जो एशिया विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित होगा और इस दौरान 900 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, युवाओं की सुविधा के लिए 25 बहुद्देशीय विपणन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

"लैंगशिप नेशनल स्किल क्वालीफिकेसन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) जिसमें 52000 युवाओं के कौशल उन्नयन तथा राज्य विस्तृत प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली संचालन की स्थापना के लिए पक्तिबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। एनएसक्यूएफ में 5 व 6 स्तर का व्यावसायिक प्रशिक्षण 8-10 पॉलिटैक्निकों तक बढ़ाया जाएगा और इनमें 4800 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

बैठक में शिमला में कौशल उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने तथा हिमाचल प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने के लिए 18 औद्योगिक इकाईयों के साथ समझौता ज्ञापन करने पर सहमति बनी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा कुशल मानव शक्ति की मांग भी पूरी होगी।

परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी.एस. बाली ने युवाओं को विभिन्न उद्योगों में 6-6 माह प्रशिक्षुता प्रदान करने की सलाह दी ताकि उन्हें उन्हीं इकाईयों में नौकरी मिल सके, जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होने कहा कि निगम द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य प्रशिक्षुता के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कौशल विकास, प्रशिक्षण समाज के सभी वर्गों को रोजगार के लिए रोड़ मैप तैयार करने के निर्देश दिए। हि.प्र. कौशल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा अब तक पूरी की गई गतिविधियों तथा परिणामों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2352 करोड़ खर्चः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य में योजना के आरम्भ होने से अभी तक 3342 बस्तियों को जोड़ने के लिए 1975 कार्यों को पूरा करके अभी तक 2352 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की उन पात्र बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ना है, जिनमें अभी तक यह सुविधा नही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 163 सड़कों तथा 27 पुलों के निर्माण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 649 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1165 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कर 45 बस्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। वीरभद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि वर्ष 2019 तक पात्र बस्तियों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जा सके। उन्होंने संबंधित जिला प्रशासन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सड़कों के तीव्र निर्माण के लिए लाभार्थियों से सम्पर्क करके उन्हें स्वेच्छा से भूमि दान करने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को स्वीकृत करवाने को कहा।

अनुराग ठाकुर ने 17 एनएच को मंजूरी देने पर नितिन गडकरी को दिया धन्यवाद

शिमला/शैल। हमीरपुर सांसद और बीवाईजेएम के प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में 17 राष्ट्रीय राजमार्गो को स्वीकृति देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हाल में धर्मशाला में हुई एक प्रेसवार्ता में गडकरी ने 1368.20 किलोमीटर लबे राष्ट्रीय राजमार्गो (एनएच) को मंजूरी देने की घोषणा की थी।

इस संबंध में अनुराग सिंह ठाकुर ने नितिन गडकरी के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की और कहा, "मैं नितिन गडकरी जी और केंद्र सरकार को 17 राष्ट्रीय राजमार्गो को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इन परियोजनाओं से निश्चित तौर पर राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे राज्य के ट्रेड और बिजनेस का विस्तार भी होगा।"

15 राष्ट्रीय राजमार्गों में से छह अनुराग सिंह ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जो इस प्रकार हैं . 57 किमी लंबा भोटा- जानहा -कलखवाल -नेरचौक मार्ग, 47 किलोमीटर लंबा रानीताल- कोटला, 43.2 किलोमीटर लंबा चमरवेन-जहू -सरकाघाट, 59 किलोमीटर लंबा हमीरपुर-सुजानपुर -आलमपुर -पालमपुर, 30 किलोमीटर लंबा थाना कलां-बनगाना-जंक्शन, 65 किलोमीटर लंबा नादौन-तीरा सुजानपुर-संढोल-कंडपत्तन मार्ग।

सिरमौर जिला के लिए 73 करोड़ की 19 सड़क परियोजनाऐं स्वीकृत:विनय कुमार

शिमला/शैल। सिरमौर जिला के लिए सरकार द्वारा 73 करोड़ की 19 सड़क परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है जिनमें से 60 करोड़ की राशि 12 सड़कों के निर्माण और 13 करोड़ की राशि सात पुलों के निर्माण पर व्यय की जाएगी ।

यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण विनय कुमार ने शिमला सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में सिरमौर जिला के लोक निर्माण अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी ।

उन्होने कहा कि सिरमौर जिला की 228 पंचायतों में से 226 पंचायतों के 731 गांव को सड़क सुविधा से जोडा दिया गया है, और शेष दो पंचायतें नावशी और पलहोड़ी को आगामी छः मास के भीतर जोड़ दिया जाएगा। उन्होने कहा कि सिरमौर जिला में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाने को प्राथमिकता दी गई जिसके फलस्वरूप जहां लोगों को आवागमन की सुविधा मिली है वहीं पर विशेषकर किसानों को अपने उत्पाद मण्डियों पहूंचाने की सुविधा उपलब्ध हुई है ।

उन्होने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सिरमौर जिला के लिए 239 करोड़ की 159 सड़क परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है, जिनमें से 136 सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिस पर अभी तक 65 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के तहत 227 करोड़ की 85 सड़क परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है जिनमें से 56 सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिस पर अब तक 113 करोड़ की राशि व्यय की गई है। उन्होने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के तहत 80 करोड़ की 19 सड़क परियोजनाऐं स्वीकृत हुई है।

विनय कुमार ने जानकारी दी कि गत तीन वर्षो के दौरान 113 किमी नई सड़को का निर्माण करके 11 गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त 180 किमी लंबी सड़कों को पक्का, 242 किमी सड़कों में कॉस ड्रेनेज, 236 किमी लंबी सड़क में पुनः तारकोल बिछाया गया। इसके अतिरिक्त सात पुल और 75 सरकारी भवनो का निर्माण पूरा किया गया ।

सीपीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई स्वीकृत की गई सड़क परियोजनाओं की टैंडर प्रक्रिया पूर्ण करके सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ किया जाए, ताकि सिरमौर का कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला की सड़कों की मुरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर समयबद्ध किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके।

केरल कपरियार टाईगर रिज़र्व की पांच सदस्य टीम हिमाचल के दौरे पर

शिमला/शैल।जी. हरी कुमार, भा.व.से., प्रधान मुख्य अरण्यपाल (व.प्र.) के नेतृत्व में केरल के परियार टाईगर रिज़र्व (Priyar Tiger Reserve) की पांच सदस्य टीम हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची। केरल से आई टीम ने वन विभाग के मुख्यालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की जिसकी अध्यक्षता ठाकुर सिंह भरमौरी वन एवं मत्स्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ने की।

इस अवसर पर केरल से आई टीम ने परियार टाईगर रिजर्व के बारे में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, उन्होंने वहां चल रहे ईको-टूरिज्म व वन्य प्राणी संरक्षण के कार्यो के बारे में भी बताया। वन मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि वे भी हिमाचल प्रदेश में केरल के तरह कार्य करें तथा जिस तरह परियार में वन्य प्राणी संरक्षण के साथ-साथ ईको-टूरिज्म कार्य किये जा रहे हैं उसी तरह वे भी हिमाचल में ईको-टूरिज्म की सम्भावनाओं को तलाशें। उन्होनें कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपार वन विविधता प्रदान की है जिसका उपयोग हमें प्रकृति पर्यटन को बढ़ाने के लिये करना चाहिये। केरल का प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पौंग डैम, खजियार, कालाटोप, धर्मशाला इत्यादि का भी दौरा करेगा।

खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सामंजस्य में हों ....महात्मा गांधी

नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश

प्रदेश सरकार मछली उत्पादन के समुचित दोहन की दिशा में कारगर प्रयास कर रही है। कृषि एवं बागवानी के साथ मछली व्यवसाय लोगों की आर्थिकी को मजबूत बनाने में अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित हो रहा है। प्रदेश में मत्स्य विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न जलाश्यों एवं मत्स्य स्त्रोतों में 'मछली उत्पादन' बढ़ाना है। मछली एक प्रोटीनयुक्त आहार होने के साथ खाद्य–सुरक्षा, गरीबी–उन्मूलन व स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने में अहम् भूमिका अदा कर रहा है।

प्रदेश के मछली उत्पादन में 9.2 प्रतिशत की बढ़ौतरी

स्वरोजगार के साधन के रूप में विकसित हो रहा है मत्स्य उत्पादन

प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में कुल 11798.72 मीट्रिक टन मछली का रिकार्ड उत्पादन हुआ जो वर्ष 2014–15 के मुकाबले 1062.61 मीट्रिक टन अधिक है और इस प्रकार उत्पादन में 9.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मछली के रिकार्ड उत्पादन के चलते प्रदेश में 109.80 करोड़ रुपये का आर्थिक कारोबार संभव हुआ है। राज्य में वर्ष 2015–16 के दौरान 417.23 मीट्रिक टन ट्राउट मछली की पैदावार हुई, जो वर्ष 2014–15 के मुकावले 61 मीट्रिक टन अधिक है। पूर्व की भांति गोविंदसागर जलाशय ने राष्ट्र के बड़े जलाशयों में प्रति हैक्टेयर सर्वाधिक मछली उत्पादन का रिकार्ड बरकरार रखा है। मत्स्य विभाग ने वर्ष 2015–16 में कुल 465.59 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।

मछली बीज मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का एक मुख्य घटक है, इसके तहत गत वर्ष प्रदेश में 581.73 लाख कार्प बीज तथा 17.50 लाख ट्राउट बीज का उत्पादन हुआ जो वर्ष 2014–15 की तुलना में क्रमश: 335.74 लाख व 6.39 लाख अधिक है। यह उपलब्धि सरकार के प्रयासों से निजी क्षेत्र के मछली पालकों को मछली बीज उत्पादन क्षेत्र से जोड़ने से संभव हो पाई है। निजी क्षेत्र में मछली बीज व मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में तीन कार्प हैचरियां, पांच हैक्टेयर के नर्सरी तालाब व 29 हैक्टेयर के बड़े मछली तालाब, दो मत्स्य आहार संयत्र, मत्स्य फार्म देवली (ऊना) व सुलतानपुर (चंबा) में स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, दो नई मत्स्य पालक सहकारी सभाओं का पंजीकरण कर उनके माध्यम से मछली दोहन के उपरांत उसके सही रख–रखाव व मूल्यवर्धक उत्पाद बनाने के लिए संयत्र व बर्फ के कारखाने भी स्थापित करवाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष ट्राउट मछली के आखेट का आनंद उठाने के लिए 2400 तथा महाशीर मछली के आखेट के लिए 1258 'ऐंगलर' प्रदेश में आए।

प्रदेश के जलाशयों में मछली के रख–रखाव के लिए सरकार द्वारा 'शीत कड़ी' ('कोल्ड–चेन') प्रदेश में आरंभ की गई जिसके अंतर्गत मत्स्य आवतरण केन्द्र भवनों का आधुनिकीकरण, बर्फ के कारखानों की स्थापना तथा सभी मछुआरों व मत्स्य सहकारी सभाओं को 'इंसुलेटिड बॉक्सज' का नि:शुल्क

वितरण किया गया। इसके परिणामस्वरूप मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने वाली मछली के मूल्यों में अपार वृद्धि हुई है। प्रयोगात्मक आधार पर प्रदेश के गोविंदसागर एवं पौंग जलाशयों में 4–4 पिंजरों का एक सैट स्थापित कर एक नई मछली प्रजाति 'पैंगाशियुच्छी' का पालन 'केज फिश कल्चर' योजना के अन्तर्गत आरंभ किया गया है।

मत्स्य विभाग राज्य में मत्स्य विकास के लिये नवीन वैज्ञानिक तरीकों को अपना रहा है। गत वर्ष बिलासपुर में 'नैशनल वर्कशाप ऑन डिवल्पमेंट आफ फिशरीज विज– ए–विज–ब्लू रिवोलूशन एण्ड वैल्यू एडीशन' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे विभाग को वैज्ञानिक ढंग से मछली उत्पादन करने का मार्गदर्शन मिला। मछली उत्पादन में सरकार के इन्हीं सघन प्रयासों के चलते प्रदेश मत्स्य विभाग को वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 'बैस्ट इनलैंड फिशरीज रिजरवायर कैटगरी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सरकार के दिशा–निर्देशों में मत्स्य विभाग ने प्रदेश में मछली पालन के विकास के लिए कई नई योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनमें जलाशयों में 'शीतकड़ी' की स्थापना, आदर्श मछुआरा–गांव आवास योजना, 'एक्वाकल्चर डिवेल्पमेंट इन्टैग्रेटिड–अप्रोच', 'मोबाईल फिश मार्किटिंग' शामिल हैं। साथ ही मछली दोहन के उपरांत इसके सही रख–रखाव व मूल्य–वर्धक उत्पादों को तैयार करने के लिए नए संयंत्र स्थापित कर विभाग ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किये हैं। इसके अतिरिक्त, समस्त विभागीय मत्स्य बीज फार्मों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण व नए फार्मों के निर्माण से मछली बीज उत्पादन में बढौतरी के चलते प्रदेश में एक सशक्त नील क्रांति आई है।

मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर में विभाग द्वारा 'मछियाल' महाशीर मछली बीज फार्म तथा कुल्लू जिले के बंजार में 'हामनी' ट्राउट फार्मों को इस वर्ष से चालू करने के हर संभव प्रयास जारी हैं। प्रदेश की 'सुनहरी महाशीर' मछली के प्रजनन हेतु मछियाल फार्म पर विभाग द्वारा परिपक्व मछली तैयार की गई है तथा इस प्रजाति की मछली का प्रजनन करवाने के लिए विभाग विशेषज्ञ महाशीर डा. एस.एन. ओग्ले की सेवाएं ले रहा है, जिनकी मदद से इस वर्ष के अन्त तक इस तकनीक के इजाद होने की पूरी संभावना है। इस तकनीक के शुरु होने से मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में विभाग कड़ी मेहनत कर नई उपलब्धियां हासिल करने के लिये निरन्तर प्रयासरत है।

सम्पादकीय

उत्तराखण्ड से सबक लेना होगा

उत्तराखण्ड में अन्ततः राष्ट्रपति शासन हट गया है। क्योंकि शक्ति परीक्षण में कांग्रेस बहुमत पाने में सफल हो गयी। उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ पहले वहां के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी गयी। इस बीच स्टिंग आपरेशन हुए जिसको लेकर सी.बी.आई. की जांच चल रही है। इसी बीच राष्टपति शासन के खिलाफ फैसला देने वाले न्यायधीश को लेकर सोशल मीडिया में हर तरह का प्रचार और प्रतिक्रियाएं भी सामने आयी और संभवतः इसी सबके कारण उनका वहां से तबादला भी हो गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी इस फैसले को पलट नहीं सका है। उत्तराखण्ड में राजनीतिक तौर पर जो कुछ घटा और उसका जो भी अन्तिम परिणाम शक्ति परीक्षण में सामने आया है उसे राजनीतिक दलों की अपनी–अपनी राजनीति के तौर पर देखा जा सकता है। उसके पक्ष और विरोध में अपने–अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरह का प्रचार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आया है वह पूरी व्यवस्था के लिए एक गम्भीर संकेत और संदेश है जिसके परिणाम भयानक और दूरगामी होंगे। क्योंकि यह प्रतिक्रिया फैंसले पर ना होकर फैंसला देने वाले के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर थी। यह न्यायधीश एक अरसे से उच्च न्यायपालिका में है और दर्जनों मामलों में फैंसले दिये होंगे लेकिन आज तक इस तरह उनके खिलाफ पहले कभी नहीं आया।

इसमें चिन्ता जनक सवाल यह उभरता है कि क्या जब भी राजनीतिक हितों के खिलाफ कोई ऐसा फैसला देगा तो क्या उसका इस तरह से चरित्र हनन किया जायेगा? फिर यदि न्यायाधीश के खिलाफ सही में ही ऐसा कुछ था तो फिर उसका विरोध पहले क्यों नहीं किया गया। आज उत्तराखण्ड के राष्ट्रपति शासन का लाभ केवल भाजपा को मिलना था। इस लाभ के लिए ही विधानसभा को भंग किये बिना राष्ट्रपति शासन लगाया था ताकि आगे चलकर चुनावों से पहले ही वहां पर भाजपा सरकार बना लेती। लेकिन जब उच्च न्यायालय के फैसले से बाजी पलट गयी तो न्यायधीश को ही निशाने पर ले लिया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रचार के पीछे भाजपा/ संघ के समर्थकों की ही भूमिका थी। इससे भाजपा और संघ की छवि को लेकर आने वाले समय में यह प्रचारित होता चला जाएगा कि यदि इनके राजनीतिक हितों के खिलाफ कहीं पर भी इस तरह का कुछ घटता है तो उसको लेकर यह लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। क्योंकि भाजपा/संघ के किसी भी बड़े ने इस तरह के प्रचार की निन्दा नहीं की है।

अभी भाजपा को देश भर में स्थापित होने में समय लगेगा भले ही लोकसभा में उनके पास 282 सीटें अपनी अकेली हैं। लेकिन जब तक राज्यों की सत्ता उनके हाथ में नही आ जाती है तब तक उसके हिन्दुवादी स्थापनों के प्रयासों को देश स्वीकार नहीं करेगा। आज राजस्थान में जिस तरह से स्कूली पाठ्यक्रम से देश के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया गया है वह भी उत्तराखण्ड़ के न्यायाधीश के खिलाफ किये जा रहे प्रचार जैसा ही प्रयास है। ऐसे ही गुजरात में दीनानाथ बत्रा की पुस्तकों को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का कदम है। भाजपा को केन्द्र की सत्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ठोस कड़ी कारवाईयां करने की उम्मीद में मिली है। लेकिन अभी दो वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार के अतिरिक्त कुछ भी ठोस नहीं किया जा सका है। भाजपा जिस तरह से नेहरू गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है उससे उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बल्कि इस तरह के प्रयासों से राहुल/सोनिया को और ताकत मिलेगी। जिस तरह से उत्तराखण्ड में सरकार गिराने का प्रयास किया गया यदि वैसा ही प्रयास किसी और राज्य में किया गया तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। यदि भ्रष्टाचार के ठोस मामलों में कुछ एक भाजपा नेताओं और कुछ कांग्रेस के मुख्यमन्त्रियों के खिलाफ तुरन्त कारवाई की जाती है तो उससे ही भाजपा और मोदी दोनों को लाभ मिलेगा अन्यथा नही है।

SDM अर्की के आदेश के बावजूद गरीब मनसाराम की फरियाद पर अंबुजा ने नहीं की कोई कारवाई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस के बड़े नेताओं व नौकरशाहों के बूते सीमेंट के कारोबार की 'किंग'बनी अंबुजा सीमेंट कपनी पिछले अढाई सालों से एक गरीब मनसाराम को तीन चार लाख रुपए के लिए तरसा रही है। आलम ये है कि वीरभद्र सिंह सरकार के बाबू एसडीएम अर्की के आदेशों को भी ये बड़े कारोबार वाली सीमेंट कंपनी भाव नही दे रही है। उनके 2015 से दिए जा रहे आदेश सिरे नही चढ़ पाए है। इसलिए अब मई 2016 में गरीब मनसा राम ने फिर एसडीएम को चिट्ठी लिख कर मुआवजे दिलाने की गुहार लगाई है। ?

मामला जिला सोलन अर्की के दाड़लाघाट के गांव सुल्ली का है। जनवरी-फरवरी 2014 में अंबुजा कंपनी ने गांव सुल्ली में मनसाराम की गौशाला के समीप बिजली का डीजे सेट लगा दिया। ताकतवर डीजे सेट के चलने से कंपन हुई तो गौशाला में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई। ये डीजे सेट आज भी कई कई घंटे यहां चलता है। इससे ये गौशाला अनसेफ हो गई। गरीब मनसा राम फरियाद लेकर कभी अमीर अंबुजा कंपनी तो कभी एसडीएम अर्की के आगे फरियाद करते रहे कि उनकी गौशाला अंबुजा कंपनी के डीजे सेट की कंपन से अनसेफ हो गई है। चूंकि मनसाराम की मुख्यमंत्री वीरभद्र सिह व भाजपा नेताओं तक पहुंच नही थी तो उन्हें न मुआवजा मिला और न ही अंबुजा कंपनी ने गौशला ही बना कर दी। ये मुआवजा आज तक भी नही मिला है। फरियादें जारी है।

11 फरवरी 2014 को मनसा राम ने एसडीएम को चिटठी लिखवी। इस

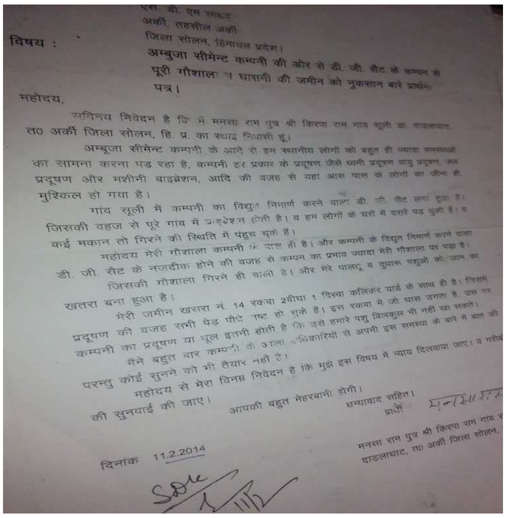

एस. डी. एम साहब

अर्की, तहसील अर्की

जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

विषय : अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी की ओर से डी. जी. सैट के कम्पन से पूरी गौशाला व घासनी की जमीन को नुकसान बारे प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं मनसा राम पुत्र श्री किरपा राम गांव सूली डा. दाड़लाघाट त० अर्की जिला सोलन, हि. प्र. का स्थाई निवासी हूं।

अम्बूजा सीमेन्ट कम्पनी के आने से हम स्थानीय लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कम्पनी हर प्रकार के प्रदूषण जैसे ध्वनी प्रदूषण वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और मशीनी वाइब्रेशन, आदि की वजह से यहां आस पास के लोगों का जीना ही मुश्किल हो गया है।

गांव सूली में कम्पनी का विद्युत निमार्ण करने वाला डी. जी. सैट लगा हुआ है। जिसकी वहज से पूरे गांव में वाइब्रेशन होती है। व हम लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी है। व कई मकान तो गिरने की स्थिति में पंहुच चुके हैं।

महोदय मेरी गौशाला कम्पनी के पास ही है। और कम्पनी के विद्युत निमार्ण करने वाला डी. जी. सैट के नजदीक होने की वजह से कम्पन का प्रभाव ज्यादा मेरी गौशाला पर पड़ा है। जिसकी गौशाला गिरने ही वाली है। और मेरे पालतू व दुधारू पशुओं को जान का खतरा बना हुआ है।

मेरी जमीन खसरा नं. 14 रकबा 2बीघा 1 बिस्वा कलिंकर यार्ड के साथ ही है। जिसमें प्रदूषण की वजह सभी पेड पौधे नष्ट हो चुके हैं। इस रकबा में जो घास उगता है उस पर कम्पनी का प्रदूषण या धूल इतनी होती है कि उसे हमारे पशु बिलकुल भी नहीं खा सकते। मैंने बहुत बार कम्पनी के आला अधिकारियों से अपनी इस समस्या के बारे में बात की परन्तु कोई सुनने को भी तैयार नही है।

महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे इस विषय में न्याय दिलवाया जाए। व गरीब की सुनवाई की जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

मनसा राम

मनसा राम पुत्र श्री किरपा राम गांव सूली डा. दाड़लाघाट, त० अर्की जिला सोलन.

दिनांक 11.2.2014

चिटठी पर एसडीएम अर्की ने गौर किया और नायब तहसीलदार दाड़लाघाट को 22 फरवरी 2014 को ये चिट्ठी भेज कर इस मामले की छानबीन कर तथ्यों के साथ रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय को भेजने के आदेश दिए। यहां से ये चिटठी 18 अप्रैल 2014 को निरीक्षण के लिए पटवारी को भेजी गई। फिर 3 जून 2014 को अर्की के तहसीलदार गिरिश एम सकलानी ने एसडीओ पीडब्ल्यूडी को लिखा कि नायब तहसीलदार दाडला ने छानबीन की जिसमें पाया गया है कि अंबुजा सीमेंट कंपनी के डीजे सेट से मनसा राम की गउशाला में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई है। इसके अलावा घास व फसलों को भी नुकसान हुआ है।

तहसीलदार ने एसडीओ पी डब्ल्यूडी दाड़लाघाट को आदेश दिए कि वो नुकसान की आकलन रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के आफिस को भेजें। नायब तहसीलदार ने ये रिपोर्ट तैयार कर इसकी प्रति एसडीएम व अंबुजा कंपनी को भी भेजी । अंबुजा कंपनी ने मनासाराम को नुकसान की एवज में कोई मुआवजा नही दिया।?

अर्की प्रशासन ने 14 मई 2015 को नुकसान की आकलन रिपोर्ट बनाकर एसडीएम अर्की को दे दी । ये नुकसान करीब तीन लाख रुपए का बना। हालांकि इसमें घासनी को होने वाले नुकसान को शामिल नही किया गया था। लेकिन नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि घासनी बर्बाद हो गई है।

आकलन रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम अर्की ने 8जून 2015 को अंबुजा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को लिखा की मनसा को अंबुजा कंपनी की ओर से हुए नुकसान की आकलन रिपोर्ट उन्हें भेज रहे है। एसडीएम ने इस मसले पर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए। लेकिन ताकतवर इस कंपनी ने एसडीएम की आदेशों को ठेंगा दिया। इसके बाद एसडीएम ने 10 दिसंबर 2015 को फिर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। लेकिन अंबुजा कंपनी प्रबंधन ने एसडीएम के आदेशों को कोई कोई भाव नही दिया।

चूंकि मनसा राम की भाजपा , कांग्रेस व वामपंथियों में से किसी तक भी कोई पहुंच नही थी सो आरटीआई व वकील का सहारा लिया गया। एसडीएम कार्यालय अर्की से खूब सारा पत्रचार हुआ लेकिन कही कुछ नही हुआ। अर्की में भाजपा, कांग्रेस के एक से एक दिग्गज नेता है जिनमें वीरभद्र सिंह से लेकर धूमल तक के आगे वो पलक-पावड़े बिछाने को हर दम तैयार रहते है। लेकिन जब जेपी व अंबुजा जैसी कंपनियां मजदूरों व स्थानीय गरीब लोगों को मनसाराम की तरह सताते हैं तो ये सारे नेता दुबक जाते है। ऐसे में एसडीएम की चिटिठयां ये कारोबारी घराने क्या जाने।

एसडीएम अर्की की ओर से मनसा राम को मुआवजा दिलाने बारे अंबुजा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंड को ये चिटठी लिखवी

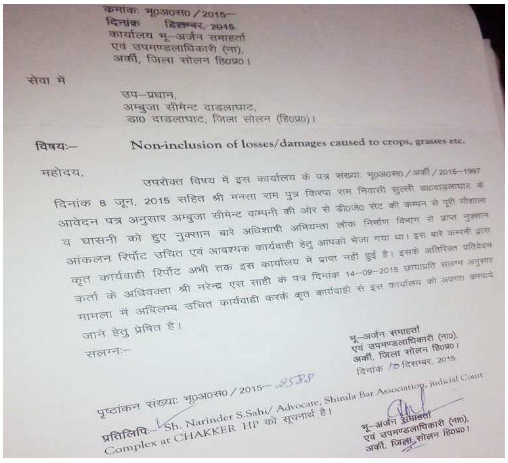

क्रमांक: भू०अ०स० / 2015—

दिनांक दिसम्बर, 2015.

कार्यालय भू—अर्जन समाहर्ता

एवं उपमण्डलाधिकारी (ना),

अर्की, जिला सोलन हि०प्र०।

सेवा में

उप—प्रधान,

अम्बुजा सीमेन्ट दाडलाघाट,

डा० दाडलाघाट, जिला सोलन (हि०प्र०)।

विषय:— Non-inclusion of losses/damages caused to crops, grasses etc.

महोदय,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्र संख्या: भू०अ०स० / अर्की / 2015—1997 दिनांक 8 जून, 2015 सहित श्री मनसा राम पुत्र किरपा राम निवासी सुल्ली डा०दाडलाघाट के आवेदन पत्र अनुसार अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी की ओर से डी०जे० सेट की कम्पन से पूरी गौशाला व घासनी को हुए नुक्सान बारे अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नुक्सान आंकलन रिर्पोट उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजा गया था। इस बारे कम्पनी द्वारा कृत कार्यवाही रिर्पोट अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन कर्ता के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र एस साही के पत्र दिनांक 14—09—2015 छायाप्रति संलग्न अनुसार मामला में अबिलम्ब उचित कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:—

भू—अर्जन समाहर्ता

एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0),

अर्की, जिला सोलन हि0प्र0।

दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

पृष्ठांकन संख्या: भू०अ०स० / 2015— 2588

प्रतिलिपि:— Sh. Narinder S.Sahi/ Advocate, Shimla Bar Association, judicial Court Complex at CHAKKER HP को सूचनार्थ है।

भू—अर्जन समाहर्ता

एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0),

अर्की, जिला सोलन हि0प्र0।

मनसाराम ने उन्हे चौंकाने वाला सच बताया कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट संजय वशिष्ठ न तो उनसे बात करता है और न ही फोन उठाता है। उन्होंने आरोप जड़ा कि जिनकी राजनैतिक सिफारिशें होती है कंपनी उन्ही को भाव देती है। वो गरीब आदमी है उनकी कोई नही सुनता। ये मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार पर आम व गरीब किसान की तीखी टिप्पणी है। ऐसा नही है कि धूमल के राज में ऐसा नही होता हो।

उन्होंने कहा कि उनके पास कुल तीन बीघा के करीब जमीन है। जिसमें से पौने दो बीघा पर ये गउशाला व घासनी है। गउशाला कंपनी के डीजे सेट की कंपन से अनसेफ हो गई है। जबकि यहां पर क्लींकर यार्ड होने की वजह से घास पर धूल ही धूल होती है। उसे मवेशी भी नही खाते है। कंपनी हर तरह से नुकसान कर रही है, ऐसे में आज भी वो इस गौशाला में एक गाय और भैंस बांधने का मजबूर है। कंपनी के छोटे कारिंदे आते है और पांच हजार देने की बात कहते हैं। जाहिर है तीन बीघा जमीन के टुकड़े का मालिक कोई भी किसान अंबुजा जैसी किंग कंपनी से जंग नही लड़ सकता। ये बात तो वीरभद्र सिंह के बाबूओं को निश्चित तौर पर मालूम होगी।

कंपनी के एचआर हैड अश्वनी वर्मा ने कहा कि वो इस मसले पर कुछ भी कहने को अधिकृत नही है। संजय वशिष्ठ चंडीगढ़ गए है। उनके आने पर ही बात हो पाएगी।

मनसा राम की फरियाद पर एसडीएम अर्की लायक राम वर्मा ने कहा कि इस मसले पर वो अंबुजा कंपनी से जवाब तलब करेंगे और मनसाराम को मुआवजा सुनिश्चित कराया जाएगा। हालांकि वो इस बावत क्या कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा।

बताते है कि अंबुजा कंपनी को हिमाचल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार लाए थे। बाद में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ भी कंपनी के लोगों की यारी हो गई। तब से लेकर अब तक ये दोस्ताना रिश्ते जारी है। बताते है कि जब इस फैक्टरी के लिए जमीन अधिग्रहित की थी तो अर्की के एक पटवारी ने जमीन की औसत कीमत रिकार्ड में कम दर्शा दी थी। अधिग्रहण का अवार्ड इसी कीमत पर हुआ था। बाद में ये पटवारी अंबुजा कंपनी में मुलाजिम हो गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई लेकिन मजे की बात है कि अंबुजा कंपनी के किसी भी कर्ताधर्ता को एफआईआर में शामिल नही किया गया। आखिर कोई शामिल होता भी कैसे दूसरी ओर तो सीडी कांड जैसे कारनामें हो रहे थे। अब मुकद्दमा अदालत में है। इसी औसत कीमत की वजह से यहां के किसानों को उनकी जमीन की कीमत कम मिली थी।

यहां ये महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में अंबुजा व जेपी कंपनी जैसे औद्योगिक घरानों को केंद्र व प्रदेश सरकार ने 2009 से 2014 के बीच 36 हजार करोड़ रुपए की सबसिडी व कर रियायतें दी थी। बीते दिनों सीआईआई की रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष संजय खुराना ने मीडिया को बताया था कि उद्योगों के लिए सरकार से उन्हें और रियायतें चाहिए। लेकिन मनसाराम जैसे गरीबों के लिए इन कंपनियों के खजाने क्यों बंद हो जाते हैं ये अमीरों के माइंडसेट को उदघाटित करने के काफी है।

शिमला की दुकानों में स्कूली किताबों का रेट घोटाला,SDM अर्बन करेंगे पर्दाफाश

शिमला/शैल। राजधानी की कई दुकानों में स्कूली किताबों के रेटों में सरेआम घोटाला कर दुकानदार उन्हें ज्यादा कीमतों में बेच कर चांदी कूट रहे है। जिला प्रशासन ने इस घोटाले का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी एसडीएम अर्बन को सौंपी है। लेकिन मजे की बात है डीसी रोहन ठाकुर से मंजूर हुई ये जांच एडीसी डीके रत्न के टेबल से चार दिन पहले एसडीएम एच नेगी को मार्क हो गई थी लेकिन ये अभी तक एसडीएम तक नही पहुंची है। एसडीएम अर्बन एच नेगी ने कहा कि उन्हें अभी तक जांच का आर्डर नही मिला है। आदेश मिलने पर वो जांच शुरू कर देंगे।

अतिरिक्त जिला उपायुक्त डीके रत्न ने ये खुलासा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को अभिभावकों ने शिकायत भेजी थी कि कई दुकानदारों ने स्कूली किताबों के प्रिंट रेट पर नया रेट लगा दिया । जो किताब बीस रुपए की हैं उसे सरेआम पचास रुपए में बेचा जा रहा। बीस रुपए के स्थान पर पचास रुपए का रेट लगा दिया है।

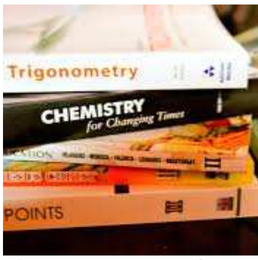

इसी तरह पचास रुपए कर किताब को सतर रुपए में बेचा जा रहा है। इस तरह लोगों की जेबों पर सरेआम डाका डाला जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक दुकानदारों की ओर से मचाई जा रही इस लूट के वीडियों भी लोगों ने प्रशासन दिखाए है। बताते है कि ये दुकानदारों का ये सारा खेल देख डीसी शिमला रोहन चंद ठाकुर ने जांच कराने का फैसला लिया। हालांकि अभी तक ये जांच शुरू नही हो पाई है। फाइलें बाबूओं के टेबलों पर इधर-उधर हो रही है। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन के अफसर जांच में क्या सामने ला पाते है।

वीरभद्र सरकार एक भी तीर्थयात्रा सर्किट हिमाचल में लाने में असफल रही है:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर, हमीरपुर सांसद और BJYM अध्यक्ष केन्द्र सरकार के मानदंडों

का अनुपाल करने में वीरभद्र की सरकार की विफलता और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में केन्द्र सरकार की सहायता का लाभ उठाने की इसकी असामर्थ्य पर खूब जमकर बरसे। अनुराग ठाकुर ने कहा, 'हिमाचल पूरे देश में देव भूमि के नाम से लोकप्रिय है। हिमाचल के मंदिरों को जोड़ते एक एक हिमालयी सर्किट स्थापित करने की केन्द्र सरकार की योजना है, लेकिन दिशानिर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार की विफलता और पिछले सालों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र नहीं जमा करवाने के कारण यह प्रक्रिया ठप्प हो गई है! मैंने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्री से निजी तौर पर कई बार मुलाकात की है और मैं उपयोग प्रमाणपत्र का मसला मुख्यमंत्री वीरभद्र के नोटिस में भी ला चुका हूँ, लेकिन मुझे केन्द्रीय आर्थिक सहायता मांगने में देरी करने का कारण समझ नहीं आ रहा है।

2014 में केन्द्र सरकार ने दो तीर्थ यात्रा योजनाएं अर्थात 'स्वदेश' और (प्रसाद) प्रारंभ की थी जो मुख्य तौर पर धरोहर स्थलों के चारों ओर पर्यटन को बढ़ावा देने तथा बुनियादी ढांचे, बेहतर संपर्क व्यवस्था को बढ़ाने तथा मंदिरों को बढ़ावा देने के लिए थी। इसने स्वदेश योजना के लिए 600 करोड़ रुपये और प्रसाद योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं, लेकिन हिमाचल भारत सरकार द्वारा पहले आबंटित निधियों के अनेक उपयोग प्रमाणपत्रों के लंबित रहने के कारण इनमें किसी भी योजना के लिए योग्य नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा, 'नरेन्द्र मोदी सरकार न केवल हमारी तीर्थ मंदिरों के आध्यात्मिक महत्त्व को जानती है, बल्कि स्थानीय आबादी के लिए आर्थिक लाभों को भी जानती है जो पर्यटन अपने साथ लाता है। कौन सी बात इन योजनाओं का लाभ उठाने से वीरभद्र सरकार को रोक रही है? यह हिमाचल सरकार की अकुशलता है कि वह पर्यटन सलकट के तहत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे लाभों का फायदा नहीं उठाना चाहती है। वीरभद्र सरकार इस राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिच्छुक क्यों है?

ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पर्यटन मंत्री से चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वालाजी, कांगड़ा में बिजेश्वर मंदिर, हमीरपुर में बाबा बालक नाथ, बिलासपुर में नयना देवी और बिलासपुर में मरकंडे मंदिर को हिमालयन सर्किट के लिए आर्थिक सहायता के अंतर्गत शामिल करने के लिए कहा है।

शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने का आग्रह:सुधीर शर्मा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने केन्द्र से आग्रह किया है कि शिमला शहर को 'अम्रुत योजना' के साथ-साथ स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भी शामिल किया जाए। इसके अलावा राज्य में धर्मशाला को भी अम्रुत योजना के अन्तर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रीवेंकैया नायडू के साथ एक बैठक के दौरान यह मांग उठाई। उन्होंने प्रदेश में विकास से जुड़े अन्य कई प्रमुख मामलों पर भी केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से कहा कि शिमला को अम्रुत योजना में शामिल किया गया है लेकिन प्रदेश की राजधानी और एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पर्यटक गंतव्य होने के कारण इसे स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भी शामिल करने की आवश्यकता है ताकि शहर का और विकास हो सके। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य का सबसे बड़ा शहर होने तथा इसके ऐतिहासिक एवं धरोहर दर्जे को ध्यान में रखते हुए शिमला को अतिरिक्त तौर पर स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया जाए।

सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किया गया है और उन्होंने मांग की कि इस शहर को अम्रुत मिशन में भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित अधिकांश शहरों को अम्रुत योजना में भी रखा है, इसलिए प्रदेश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला को भी इस योजना में शामिल किया जाए।

उन्होंने कुल्लू-मनाली और मंडी-सुंदरनगर जैसे छोटे कस्बों को भी सामूहिक रूप से अम्रुत योजना में शामिल करने की भी मांग उठाई।

सुधीर शर्मा ने धर्मशाला मल निकासी योजना के लिए धनराशि आवंटित करने का मामला भी उठाया। उन्होंने अवगत करवाया कि धर्मशाला नगर निगम ने धर्मशाला शहर के शेष बचे क्षेत्रें को सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए 101.36 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विशेष श्रेणी राज्य हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए तथा केन्द्रीय सहायता का आवंटन 90:10 के आधार पर किया जाए।

नायडू ने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

NATIONAL HEALTH MISSION

अपने बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाएं

मानव सेवा

टीके का नाम	कब देना है
बी.सी.जी.	जन्म के समय/1½ माह
हैपेटाइटिस बी (बर्थ डोज)	जन्म के समय/जन्म से 24 घंटे के भीतर
ओपीवी-0	जन्म के समय/जन्म से 15 दिन के भीतर
ओपीवी-1,2,3	1½ माह, 2½ माह, 3½ माह की उम्र पर
ऑरल ड्रॉप्स रोटावायरस वैक्सिन-1,2,3 (ROTA)	1½ माह, 2½ माह, 3½ माह की उम्र पर
इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सिन (IPV)	3½ माह की उम्र पर
पैंटाविलैंट 1, 2, 3	1½ माह, 2½ माह, 3½ माह की उम्र पर
मीजल्स	9 – 12 माह की उम्र में
विटामिन ए (1 डोज)	9 – 12 माह की उम्र में (मीजल्स के टीके के साथ)
डीपीटी बूस्टर	16 –24 माह की उम्र में
मीजल्स बूस्टर	16 – 24 माह
ओपीवी बूस्टर	16 –24 माह की उम्र में
विटामिन ए (2-9 डोज)	16वें माह पर डीपीटी/ओपीवी बूस्टर के साथ इसके बाद हर 6 माह में 5 साल की उम्र तक.
डीपीटी बूस्टर	5-6 साल की उम्र में
टी.टी.	10 साल एवम् 16 साल की उम्र में

APPEAL

Dispose your e-waste properly !

If not disposed properly and safely, this may lead to health and environmental hazards !!

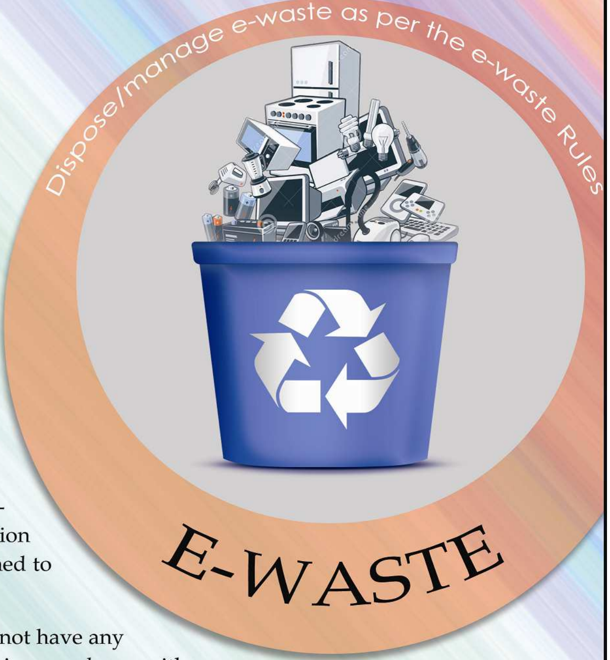

Attention

Producer, consumer or bulk consumer, collection centre, dismantler and recycler of e-waste

- **Producer** of e-waste shall ensure collection of e-waste during the manufacture of electrical and electronic equipment and channelizing it to registered dismantler or recycler. Producer shall set up collection centres.
- **Collection center** shall ensure to store the e-waste in secured manner so that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste.
- **Consumer or bulk consumer** of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall ensure that e-waste generated by them is channelized to authorized collection centre(s) or registered dismantler(s) or recycler(s) or is returned to the pick-up or take back service provider.
- **Dismantler** shall ensure that dismantling process does not have any adverse effect on health and environment and processes are in accordance with the standards/guidelines published by CPCB.
- **Recycler** shall ensure that recycling processes are in accordance with standards/guidelines of CPCB and residue generated is disposed off in a hazardous waste treatment storage/disposal facility.
- Every producer, collection centre, dismantler and recycler are required to obtain authorization and/or registration from the State Pollution Control Board.

For details please visit: http://www.moef.nic.in/legis/hsm.htm

- **E-WASTE** (Management and Handling) Rules 2011 have become effective from 1st May 2012.
- *Non-compliance of the provisions of these Rules shall attract penal action under Environment (Protection) Act, 1986.*

HP State Pollution Control Board

Issued in public interest...

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015